(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Rajasthan ..	Millers/Dealers	75% in Sriganganagar district 50% rest of the state. (25% export levy on paddy).
14.	Tamil Nadu	.. Millers/Dealers	50% (50% export levy on paddy)
15.	Tripura	.. —	—
16.	Uttar Pradesh	.. Millers/Dealers	60% (Western Uttar Pradesh) 40% (some districts in East Uttar Pradesh)
17.	West Bengal	.. Millers	30%
18.	Chandigarh	.. Millers/Dealers	75%
19.	Delhi	.. Millers/Dealers	75%
20.	Pondicherry	.. Millers/Dealers	30% transport levy on paddy/ rice. 20% purchase levy on paddy.

*Export levy on paddy removed w.e.f. 5th January, 1993.

खाद्यान्नों का एक राज्य से दूसरे राज्य में लाया ले जाया जाना

@ 1335. **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्यान्नों के लाये ले जाए जाने पर लगी रोक को हटाने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पर लगी रोक हटा ली गई है;

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों में यह रोक अभी भी लगी हुई है;

(घ) किन-किन राज्यों से रोक हटा ली गई है; और

(ङ) कतिपय राज्यों द्वारा इन रोकों को न हटाये जाने के क्या कारण हैं और इन रोकों को कब तक हटा लिए जाने की संभावना है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार खाद्यान्नों (गेहूं, लेवी मुक्त चावल, मोटे अनाजों और दालों) के अन्तर्राज्यीय तथा अन्तः राज्यीय संचलन के लिए समस्त देश को एकल खाद्य जोन माना जाता है ।

सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को 26-3-93 को समस्त देश को एक खाद्य जोन मानने की इस राष्ट्रीय नीति के बारे में सूचित किया गया था । उनसे अनुरोध किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि खाद्यान्नों के संचलन में कोई बाधा नहीं होने पाए । उन्हें यह भी परामर्श दिया गया था कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के लिए औपचारिक प्रस्ताव भेज कर ऐसे सांविधिक प्रतिबंध संबंधी उपबंधों को हटा दें जिनकी वजह से खाद्यान्नों के अन्तर्राज्यीय और अन्तः राज्यीय संचलन में बाधा पड़ती हो ।

उत्तर प्रदेश, गोआ, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम,

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न सं० 660, 3 मई, 1993 से स्थानांतरित ।

पंजाब, त्रिपुरा और मिजोरम की सरकारों ने सूचित किया है कि उनके राज्यों में संचलन संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं हैं। शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

उपलब्ध सूचनानुसार, कर्नाटक में सीमावर्ती क्षेत्रों (5 किलोमीटर की पट्टी) से राज्य के बाहर किसी स्थान और सीमावर्ती क्षेत्र के अन्दर भी धान/चावल का संचलन परमिट जारी कर विनियमित किया जाता है। तमिलनाडु में, जो लाइसेंसशुदा व्यापारी चावल अथवा धान राज्य के बाहर भेजना चाहता है, उसे बाहर भेजी जाने वाली चावल अथवा धान की कुल मात्रा के बराबर मात्रा सरकार को वसूली मूल्य पर लेवी के प्रति सुपुर्द करनी होती है। चावल की अधिकतम वसूली करने की दृष्टि में आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों और चण्डीगढ़ प्रशासन ने भी धान के अन्तर्राज्यीय संचलन पर प्रतिबंध लगाए हैं। राजस्थान और पांडिचेरी ने भी धान पर क्रमशः 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की निर्यात लेवी लगाई है।

Literacy Drive through Students

1336. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE :
SHRI V. NARAYANASAMY:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Delhi University proposes to spread literacy drive through its students; and

(b) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) Yes, Sir.

(b) The students of Delhi University have been participating in the literacy programmes through its Department of Adult & Continuing Education and the NSS. During 1992-93, about 1,000 students were involved in literacy programmes taken up in certain localities and villages in Delhi. The Universersity proposes to continue these activities and also to involve students on much wider scale in Adult Education Programmes in the coming years.

Making School Education Enjoyable

1337. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE :
SHRI V.NARAYANASAMY:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a recent National Sample Survey has revealed that about one-third of school children in the age group of 6 to 14 find school education boring;

(b) if so, what are the details thereof and what are the reasons therefor; and

(c) what measures Government have taken to make the school education enjoyable ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) and (b) The National Sample Survey Organisation brought out 46th issue (January-March 1991) of 'Sarvekshana' which provides data relating to percentage of drop outs and percentage of children never enrolled and the reasons therefor. The details are given in the Statement (*See* below). One of the major rea-